बोल-सुन नहीं सकता हत्याराः कार से स्कूटी टच होने पर दिव्यांग ने ले ली जान, छाती पर बैठकर मारे कई मुक्के

दिल्ली दिल्ली के पालम इलाके में स्कूटी टच होने पर गुस्साए दिव्यांग आई10 कार चालक ने स्कूटी सवार को पीट पीटकर हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त साध नगर निवासी 30 साल के कपिल शर्मा के रूप में हुई। पुलिस ने चश्मदीद के लिए गए कार के फोटो के जरिए आरोपी की पहचान साध नगर निवासी करण अरोड़ा के रूप में की और घटना के दो घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिव्यांग है और वह बोल और सुन नहीं सकता है। पुलिस आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि 4 अक्तूबर की रात 9.30 बजे पालम गांव थाना पुलिस को सूचना मिली कि साध नगर में एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा है।

बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 05 ● नई दिल्ली ● वीरवार 09 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

वायुसेना का स्थापना दिवस आजः मुख्य आयोजन हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर, ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं पर रहेंगी निगाहें

गाजियाबाद वायुसेना आज अपना 93 वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं पर देश की नजर रहेगी। इस दौरान मुख्य आयोजन गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर होगा। यह पहला अवसर है जब वायुसेना इस आयोजन को दो हिस्सों में कर रही है। हिंडन एयरबेस पर वायुसैनिकों की परेड और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का उद्बोधन होगा जबकि लड़ाकू विमानों और हेलिकॉप्टरों के हवाई करतब का प्रदर्शन 9 नवंबर को गुवाहाटी में किया जाएगा। हिंडन पर इस बार मिग-21 भी खड़ा नजर आएगा। छह दशक की सेवा के बाद यह विमान पिछले ही दिनों वायुसेना से रिटायर हुआ है। हालांकि, इस दौरान राफेल और सुखोई-30 जैसे मारक एयरक्राफ्ट भी लोगों के मुख्य आकर्षण का विषय होंगे, जिन्होंने पाकिस्तान को मजा चखाने में अहम भूमिका निभाई। हर बार वायुसेना दिवस पर आसमान में अलग-अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरते लड़ाकू विमानों और हेलिकॉप्टरों की गर्जना सुनाई देती थी, जिसे देख दर्शकों का भी खूब मनोरंजन होता था।

इस बार समारोह का मुख्य आकर्षण वायुसेना के वो योद्धा होंगे, जिन्होंने मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के छक्के छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई। वायुसेना के इन जांबाजों ने दुश्मन के रनवे और लड़ाकू विमान तबाह कर दिए। नतीजतन पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत में ही रक्षात्मक हो गया। वायुसेना प्रमुख इन सभी एयर वॉरियर्स को सम्मानित करेंगे। साल 2021 तक वायुसेना दिवस का मुख्य समारोह हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर ही होता था, लेकिन इसके बाद यह चंडीगढ़, प्रयागराज और चेन्नई में रखा गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह थी कि सैन्य बलों को अपने मुख्य समारोह अलग-अलग शहरों में आयोजित करने चाहिए, ताकि देश के सभी हिस्सों से आम लोग इनसे जुड़ पाएं। आठ अक्तूबर को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स-डे के कार्यक्रम की वजह से डायवर्जन करने का निर्णय लिया गया है। सवेरे छह बजे से कार्यक्रम संपन्न होने तक भारी व्यावसायिक वाहनों का एयरफोर्स स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्तों पर आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान यह वाहन वैकल्पिक रास्तों से होकर निकाले जाएंगे। एडीसीपी यातायात सच्चिदानंद ने बताया कि एएलटी चौराहा से रोटरी गोलचक्कर, हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से रोटरी गोलचक्कर और रोटरी गोलचक्कर से नागद्वार की ओर, करहेड़ा कट जीटी रोड से हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर, मोहननगर से हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर, करन गेट गोलचक्कर से हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, तापमान में गिरावट; ट्रैफिक जाम, उड़ानों पर भी असर

नई दिल्ली राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है, इसके चलते बीते दो दिनों से मौसम ठंडा और खुशनुमा बना हुआ है। ऐसे में सोमवार को हुई बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को एकाएक मौसम ने करवट लेकर दिल्लीवालों को हैरान-परेशान कर दिया। सुबह सात बजे तक भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिनभर वर्षा का दौर जारी रहने वाला है। लेकिन दोपहर बाद से मौसम ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। दिन भर सूरज व बादलों के बीच लुकाछिपी चलने के बाद तेज बारिश होने लगी। इससे जगह-जगह जाम लगा तो, जलभराव ने भी परेशान किया। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ। शाम को हुई इस बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में भीषण जाम लगा। ऑफिस से निकलते जाम में फंसकर परेशान नजर आए। जहां बारिश के कारण रफ्तार पर रोक लगी वहीं खराब मौसम का असर उड़ानों पर पड़ा। दिल्ली हवाई अड्डा ने जानकारी दी कि बारिश के कारण 15 विमानों को डायवर्ट किया गया है। इनमें से आठ जयपुर, दो लखनऊ और दो को चंडीगढ़ डायवर्ट किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री कम के साथ 29. 8 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक के साथ 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में लोगों को ठंडक का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश का यह दौर पश्चिमी विक्षोभ के चलते हो रहा है। उत्तरी राजस्थान और उससे लगे हरियाणा के ऊपर एक प्रेरित निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके साथ ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 9.6 किमी ऊपर तक फैला है और ऊंचाई के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में बीते 24 घंटे में 12. 6 और मंगलवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक 5. 8 एमएम बारिश दर्ज की गई। ऐसे में पालम में 41.6 रिज में 37 पूसा में 22.5, मयूर विहार में 20, लोधी रोड में 5.8 और आया नगर में 5.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं, मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डाले तो इस माह में अब तक चार दिन बारिश हुई है।

दिल्ली से चीन भेजी जा रही लाल चंदन की 10 टन सिल्लियां पकड़ीं, दो गिरफ्तार; माल की कीमत करीब 6 करोड़

दिल्ली दक्षिण-पूर्व जिले की एसटीएफ ने 10 टन लाल चंदन की लकड़ी जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के तार अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हैं।

आरोपियों के कब्जे से जब्त की गई लकड़ियों की कीमत करीब छह करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चंदन की ये लकड़ियां चीन व अन्य देशों में भेजी जानी थीं। दक्षिण-पूर्व पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि चंदन की लकड़ी आंध्र प्रदेश के तिरुपति से तस्करी कर चीन और अन्य दक्षिण एशियाई देशों को भेजने के लिए लाई गई थी। बताया कि यह अभियान अगस्त में तिरुपति से चुराई गई लाल

चंदन की लकड़ियों के बारे में आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था। डॉ. तिवारी ने बताया कि चोरी के संबंध में तिरुपति में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों ने खुलासा किया कि चोरी की गई लकड़ियां दिल्ली ले जाई गई हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और आंध्र प्रदेश खुफिया इकाई की टीम ने सोमवार को तुगलकाबाद स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान करीब 9,500 किलोग्राम लाल चंदन की लकड़ियां बरामद की गईं और दो लोगों हैदराबाद के इरफान और मुंबई के ठाणे के अमित संपत पवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने अगस्त के पहले हफ्ते में आंध्र प्रदेश से लाल चंदन की लकड़ियां हासिल कीं और उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए ट्रकों में छिपा दिया। यह ज़ब्ती दिल्ली में हुई लाल चंदन की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। आरोपियों ने इस खेप को विदेशी बाजारों विशेष रूप से चीन और दक्षिण एशियाई देशों में भेजने की योजना बनाई थी। वहां लाल चंदन की लकड़ी औषधीय और वाणिज्यिक मूल्य के कारण बहुत ऊंची कीमत पर मिलती है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आरोपियों ने कबूल किया कि वे आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्रों से लाल चंदन की लकड़ियां लाते थे और उन्हें ट्रकों में छिपाकर ले जाते थे। बरामद लकड़ियां एक संगठित तस्करी नेटवर्क के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को भेजी जानी थीं।

बेरोजगार बस मार्शल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतने के लिए तैयार, आज जंतर-मंतर पर करेंगे प्रदर्शन

दिल्ली दिल्ली सरकार के खिलाफ बेरोजगार सिविल डिफेंस बस मार्शल सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। लगभग 10 हजार से अधिक बेरोजगार मार्शलों ने अपने स्थायी रोजगार बहाली की मांग को लेकर बुधवार को जंतर-मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का एलान किया है। इनमें महिलाएं और पुरुष जवान शामिल होंगे, जो भाजपा सरकार की चुनावी वादों को पूरा न करने पर खुली चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा की कोठी से लेकर जंतर-मंतर तक मार्च प्रदर्शन की शुरुआत कल सुबह 7:30 बजे होगी। इसके अलावा सैकड़ों बेरोजगार मार्शल दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा से मुलाकात के लिए उनके आवास पर पहुंचेंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, तब विपक्ष में भाजपा के दिल्ली विधायक विजेंद्र गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता कपिल मिश्रा ने इन्हें पूर्ण रोजगार का आश्वासन दिया था। भाजपा सरकार बनने के बाद दो महीने में पक्की नौकरी देने का वचन दिया गया था, लेकिन आठ महीने बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व बस मार्शल मुकेश पाल सिंह ने आरोप लगाया कि हमारे नेता वचन तो देते हैं, लेकिन कानों पर जूं नहीं रेंगती। मार्शलों का कहना है कि अगर भाजपा अपना वादा पूरा नहीं कर सकती, तो खुलकर कह दे। एमसीडी के जन स्वास्थ्य विभाग के डीबीसी व अन्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार नौवें दिन भी जारी है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी मांगों का समाधान नहीं करता, हड़ताल जारी रहेगी। वह बुधवार को राजघाट से लेकर दिल्ली सचिवालय तक मार्च करेंगे और अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ज्ञापन देंगे। कर्मचारियों की मुख्य मांगें समान वेतन, मेडिकल लीव और मृत्यु पर परिवार को नौकरी का प्रावधान हैं। डीबीसी से एमटीएस बनने के बाद भी वे अलग-अलग वेतन स्केल (14,000 से 27,000 रुपये) में भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले उनके परिवार की सुरक्षा के लिए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पार्षद व एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कर्मचारियों से मुलाकात का उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब से ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं, दिल्ली में डेंगू और मलेरिया का खतरा तेजी से बढ़ गया है।

राजधानी में हर घंटे खराब हो रही हैं डीटीसी की पांच बसें, विभाग ने गिनाए रोकने के कई प्रयास

दिल्ली राजधानी में डीटीसी की हालत ऐसी है कि हर घंटे में पांच बसें सड़क पर खराब हो रही हैं। हर दिन 112 से अधिक बसें सड़क पर खराब हुई हैं। 2023 और 2024 के बीच कुल 81,869 बसों के ब्रेकडाउन के मामले दर्ज हुए। यह संख्या राजधानी में सार्वजनिक परिवहन की तकनीकी और प्रबंधन स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है। साल 2025 के शुरुआती सात महीनों में ही 21,123 बसें खराब हुईं। उत्तर क्षेत्र के डिपो ने सबसे अधिक शिकायतें दर्ज कराईं। इस क्षेत्र में 8,598 बसें जनवरी से जुलाई तक खराब हुईं। रोहिणी डिपो-4 में इस साल 1,008 बसों के खराब होने के मामले सामने आए, जो 2023 में 1,824 और 2024 में 1,249 रहे थे। वहीं रोहिणी सेक्टर-37 डिपो में इस साल जनवरी से जुलाई तक 3,014 बसें खराब हुईं, जबकि 2023 में यह संख्या 686 और 2024 में 1,007 थी। नरेला डिपो में 2025 में 3,260 बसें खराब हुईं, जबकि पिछले दो वर्षों में क्रमशः 3,140 और 2,970 मामले दर्ज हुए। दक्षिणी क्षेत्र में 8,510 बस ब्रेकडाउन हुए। ओखला डिपो में 2,308 बसें इस साल जनवरी-जुलाई के बीच सड़क पर रुक गईं। यह डिपो पिछले साल ही शुरू हुआ था और पहले ही वर्ष में 3,514 बसों के खराब होने के मामले सामने आए थे। सरोजिनी नगर डिपो में 2025 में 2,139 बसें, 2024 में 3,465 और 2023 में 3,600 बसें खराब हुईं। वहीं पूर्वी क्षेत्र के राजघाट डिपो-2 में इस साल अब तक 1,049 शिकायतें मिली हैं। यह संख्या 2023 में 222 और 2024 में 480 थी। हालांकि राजघाट डिपो-1 में कमी देखी गई, यहां इस साल 642 बसें खराब हुईं, जबकि पिछले वर्षों में क्रमशः 1,700 और 1,119 मामले सामने आए थे। पश्चिमी क्षेत्र दो डिपो मूंधेला कलां इस साल 467 बसें खराब हुईं, जबकि 2023 में 391 और 2024 में 433। वहीं द्वारका सेक्टर-8 डिपो में 2025 में 1,128 बसें खराब हुईं, जबकि पिछले दो वर्षों में यह आंकड़ा 2,261 और 2,212 था। डीटीसी के अधिकारियों ने बताया कि बसों के ब्रेकडाउन की घटनाओं को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 15 मिनट में खराब बस को हटाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार किया गया है। इसके तहत 30 स्थानों पर क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात की गई हैं और 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि ट्रैफिक बाधा कम हो। सीएनजी बसों में खराबी की वजहों की जांच और समाधान के लिए प्रीवेंटीव मेंटेनेंस प्रोग्राम मजबूत किया गया है।

बच्चों को निगलता कफ सिरप और सिस्टम

मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत का मामला अब पूरे देश में चिंता का विषय है। दोनों राज्यों में 'कोल्ड्रिफ' नाम के कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत का आरोप है। इनमें से 16 मौतें मध्य प्रदेश और दो राजस्थान में हुई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'कोल्ड्रिफ' को जिम्मेदार बताते हुए इसे बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, 2022 में कफ सिरप पीने के बाद तीन देशों में 300 बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। कैसी विडंबना है कि जीवन रक्षा के लिये दी जाने वाली दवा मौत का कारण बन जाए। केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे दवाओं की गुणवत्ता की सख्त निगरानी करें और बच्चों को बिना जरूरत खांसी की दवा न दी जाए। साथ ही, जांच में कोलड्रिफ नाम के कफ सिरप में जहरीले रसायन डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई, जिसके बाद केंद्र ने तमिलनाडु की उस यूनिट का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है, जहां दवा तैयार की गई थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पीड़ित परिजनों के अनुसार बच्चों को खांसी की शिकायत थी। कफ सिरप पिलाया गया और अन्य दवाएं भी दी गईं। सिरप पीने के बाद ही बच्चों को पेशाब रुकने जैसी दिक्कतें होने लगी। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि बच्चों की किडनी फेल हो चुकी थी। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन कुछ ही दिनों में 11 मासूमों की जान चली गई। एक बच्ची की मौत के बाद नागपुर जिला प्रशासन से खबर मिली की किडनी फेल होने से जान जा रही है। जांच टीम ने तीन बच्चों की बायोप्सी की, जिसकी रिपोर्ट में किडनी नेफ्रॉन में डैमेज दिखा। आखिर कफ सिरप में जहरीले केमिकल कैसे पहुंचते है यह यक्ष प्रश्न है। जो दवा की संदिग्ध गुणवत्ता और निर्माता कंपनियों की आपराधिक लापरवाही को ही उजागर करती है। जाहिर है कि रसायनों की घातकता की मात्रा और गुणवत्ता में कोई खोट इस तरह के हादसों का सबब बना होगा। राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत की वजह का संबंध उस सिरप से बताया जा रहा है जो खांसी ठीक करने के लिये दिया गया। ये हादसे इस बात को रेखांकित करते हैं कि दवा की गुणवत्ता में चूक सामान्य उपचार को कितने जानलेवा जोखिम में बदल सकती है।

मध्य प्रदेश में जिस सिरप का इस्तेमाल हुआ, वह तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित 'श्रीसन फार्मास्युटिकल्स' की फैक्ट्री में बना था। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग ने इस फैक्ट्री से लिए गए कोलड्रिफ सिरप के सैंपल की जांच की, जिसमें 48.6 प्रतिशत डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी पाया गया। यह बेहद जहरीला रसायन है जो किसी भी फार्मा प्रोडक्ट में तय मात्रा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताया जाता है कि बच्चों को कथित रूप से मुख्यमंत्री की मुफ्त दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में एक जेनेरिक खांसी की सिरप दी गई थी। राजस्थान के भरतपुर और सीकर जिलों में जिन दो बच्चों की मौत हुई, जांच में सामने आया कि उन्हें घर पर ही कफ सिरप दिया गया था, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मृतकों के परिवारों को दवा दुकानदारों से यह सिरप मिला था। यह त्रासदी भारत की फार्मास्युटिकल निगरानी तंत्र की कोताही ही उजागर करती है। सकर हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्यों में, जो फार्मा हब के रूप में प्रमुख रूप से उल्लेखित है। महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश की 655 फार्मास्यूटिकल इकाइयों में से केवल 122 ही जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज के संशोधित शेड्यूल एम मानकों के तहत अपग्रेड करने के लिये पंजीकृत हैं।

इसका मतलब यह है कि अधिकांश फार्मा इकाइयां गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को प्रमाणित किए बिना काम कर रही हैं। ये जन स्वास्थ्य के प्रति कितनी गैर जिम्मेदार स्थिति है। यह मामला दवा निर्माण प्रक्रिया में निगरानी और परीक्षण प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करता है। देश में हर दवा बैच की जांच का नियम तो है लेकिन कई छोटी और मध्यम फार्मा इकाइयां इसे नजरअंदाज करती हैं। जो सिरप तमिलनाडु की यूनिट से निकला, उसमें डीईजी का ऊंचा स्तर संकेत है कि या तो कच्चे माल की जांच नहीं हुई, या फैक्ट्री में मिलावट को नजरअंदाज किया गया। पिछले साल देशभर में 100 से ज्यादा सिरप गुणवत्ता के अनुरूप नहीं मिले थे। सिरप में ग्लिसरीन मिलाई जाती है जिससे दवा गाढ़ी और मीठी बनती है। ग्लिसरीन वैसे तो सुरक्षित होती है लेकिन जब ग्लिसरीन की जगह या गलती से या सस्ते विकल्प के रूप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल डीईजी या एथिलीन ग्लाइकॉल यानी ईजी जैसे केमिकल उसमें मिल जाते है तो समस्या होती है। ये केमिकल असल में औद्योगिक उपयोग के लिए बने होते है जैसे ब्रेक ऑयल, पेंट, और इंजन कूलेंट। कई बार फैक्ट्रियों में टैंक, पाइपलाइन ठीक से साफ नहीं किए जाते। इससे ये पुराने औद्योगिक रसायनों के अंश ग्लिसरीन में मिल जाते हैं। कभी-कभी सप्लायर सस्ती नकली ग्लिसरीन देते हैं। जब यही दूषित ग्लिसरीन सिरप में प्रयोग होती है तो कफ सिरप जहरीला बन जाता है। बीते महीने में यूपी में आगरा से नकली दवाइयों की बड़ी खेप बरामद हुई थी। आगरा में नकली दवाओं के कारोबारियों के कनेक्शन देशभर में फैले हुए थे।हालिया मौतों के बाद बड़ा सवाल यही है कि डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, पुरानी घटनाओं के बाद भी देश में ऐसे मामले दोबारा कैसे आए, क्या फैक्ट्रियों में जांच कागजों तक सीमित है, क्या ड्रग कंट्रोल विभाग सही निरीक्षण कर रहे हैं? जवाब जांच रिपोर्ट में मिल सकता है लेकिन फिलहाल देश के लोगों में चिंता है। ऐसे हादसों को या तो कमतर दर्शाया जाता है या फिर पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि विगत में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। भारत की फार्मा कंपनियों के द्वारा तैयार सिरप से गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत का लिंक पाए जाने के बाद भारतीय दवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे। निस्संदेह, ऐसे गैर-जिम्मेदार तरीके से तैयार दवाइयों के चलते भारत की 'विश्व की फार्मेसी' के रूप में हासिल प्रतिष्ठा को ही नुकसान पहुंचा है। हमारे नियामक तंत्र को और कितने बच्चों के मरने का इंतजार है, जरूरी है इससे पहले गुणवत्ता नियंत्रण सिर्फ कागज पर नहीं व्यवहार में लागू करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने दवाइयों के गुणवत्ता मानकों को तय करने के लिए सख्त तरीके जीएमपी अनुपालन हेतु समय-समय पर निरीक्षणों के लिये कदम उठाए हैं लेकिन प्रवर्तन के स्तर पर अभी भी तमाम खामियां बरकरार हैं। विडंबना यह है कि राज्य नियामकों के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। साथ ही अक्सर दंड के प्रावधान प्रभावी नहीं होते। अतीत में भी ऐसी कई त्रासदियां हुई हैं लेकिन हमारे तंत्र ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। यह विडंबना ही है कि हमारा तंत्र जन-स्वास्थ्य के खिलवाड़ के प्रति उदासीन बना हुआ है। यह एक कटु सत्य है कि भारत की फार्मा सफलता की कहानी केवल सस्ती जेनेरिक दवाइयों पर आधारित नहीं रह सकती। हमें इसे विश्वसनीय बनाने की जरूरत है। इसके लिए मजबूत ऑडिट, लापरवाही के लिए आपराधिक जिम्मेदारी तय हो और मामलों में पीड़ितों को तीव्र न्याय मिलना चाहिए। निस्संदेह, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उनके लिये यह महज कोई सांत्वना नहीं है। उन्हें सही मायनों में सांत्वना तभी मिलेगी जब आपराधिक लापरवाही करने वालों को दंडित किया जाएगा।

सम्पादकीय...

न्यायमूर्ति गवई पर हमला !

भारत के जनमानस में देश की न्यायपालिका के प्रति अथाह सम्मान का भाव स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही रहा है, क्योंकि जब भी लोकतन्त्र के दो मजबूत खम्भे विधायिका और कार्यपालिका अपना काम करने में कोताही या लापरवाही बरतते हैं तो न्यायपालिका खड़े होकर पूरी दिलेरी के साथ इस व्यवस्था को संभाल लेती है और किसी भी प्रकार की विसंगति को परिमार्जित कर देती है। हमारी लोकतान्त्रिक प्रणाली में न्यायापालिका को न केवल स्वतन्त्र रखा गया है, बल्कि पूरे देश में कानून का राज कायम रखने की जिम्मेदारी से भी लैस किया गया है। ऐसा करके हमारे संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप से संविधान का संरक्षक ही बनाया। अतः यह बेवजह नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश दिलाते है और राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश को। क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान का संरक्षक माना जाता है। हमारे संविधान निर्माता जो यह शास्त्रीय व अद्भुत प्रणाली स्थापित करके गये हैं उसमें देश के प्रधान न्यायाधीश के पद की गरिमा व प्रतिष्ठा को भारत के राजनीतिक शासन तन्त्र से पूरी तरह निरपेक्ष रखने के प्रावधान बहुत पुख्ता तौर पर किये गये हैं। अतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हम न्यायमूर्ति अलंकरण से उच्चारित करते है और सदैव अपेक्षा करते है कि उनका कोई भी फैसला केवल संविधान की परिधि के भीतर ही होगा। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि देश पर कौन सी राजनीतिक पार्टी राज कर रही है, बल्कि इस बात से मतलब होता है कि किसी भी राजनीतिक दल की सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है या नहीं। इसकी वजह यह है कि भारत में ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा या राज्यसभा तक में लोगों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि? सबसे पहले संविधान की कसम उठा कर ही अपना-अपना काम शुरू करते हैं और ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमन्त्री पद तक का कार्यभार संभालते हैं। इसी प्रकार कार्यपालिका के भी सभी अफसर संविधान की कसम उठाते है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के सन्देह से ऊपर रखें और सुनिश्चित करें कि सर्वोच्च न्यायालय जब अपना कार्य करे तो उसके सामने भारत के सभी हिन्दू-मुसलमान केवल भारत के नागरिक हों। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत गंभीर चिन्तन व मनन करने के बाद ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया था। इसका कारण यह था कि मजहब की बुनियाद पर पृथक देश पाकिस्तान का निर्माण हो जाने के बाद भारत के लोगों पर इस देश की विविधता से भरी मूल संस्कृति को संरक्षित रखने का भार आ पड़ा था। यह संस्कृति सभी मत-मतान्तरों के लोगों को एक साथ लेकर चलने की थी। इस देश के बहुसंख्यक हिन्दू समाज में विभिन्न विचारों को मानने वालों का समावेश था। जिसमें साकार ब्रह्म की पूजा करने वालों से लेकर निराकार ब्रह्म को पूजने वाले लोग थे। यह खूबसूरती केवल भारत में ही हो सकती है कि इसमें अनीश्वरवादी धर्म भी खूब फूले-फले थे। सगुण और निर्गुण ईश्वर पूजा की इसमें खुली छूट थी। इससे भी ऊपर चरक जैसे ऋषि भी हुए जो पूरी तरह भौतिकवाद के पक्षधर थे और कहते थे कि 'ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत'। इसलिए भारत की संस्कृति में जो भी धर्म इसकी पृथ्वी पर आया वह भारत की मिट्टी की तासीर से सराबोर रहा परन्तु विगत सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री बी.आर. गवई की अदालत में उन पर एक वकील राकेश किशोर ने जूता फेंकने की हिमाकत की जिससे देश के हर नागरिक को बहुत दुख व पीड़ा का एहसास हुआ। आजाद भारत के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश पर खुली अदालत में हमला करने की यह पहली घटना थी। इससे पूर्व लगभग 24 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति के विरुद्ध ऐसी ही घटना जरूर हुई थी। मगर न्यायमूर्ति पर इस घटना का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अदालत की कार्यवाही यथावत जारी रखी और निर्देश दिया कि राकेश किशोर को गिरफ्तार न किया जाये। श्री गवई बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और सभी धर्मों का एक समान रूप से सम्मान करते हैं। वह एक जमाने में रिपब्लिकन पार्टी के कर्णधार माने जाने वाले नेता स्व. रामकृष्ण सूर्यभान गवई के पुत्र है जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। वह सामाजिक न्याय व दलितोत्थान के बहुत बड़े अलम्बरदार थे। अतः श्री गवई की पारिवारिक विरासत बहुत समृद्ध व प्रगतिशील विचारों की है। उनका खजुराहो मन्दिरों के एक मन्दिर में स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा के परिमार्जन करने के बारे में दायर याचिका पर यह टिप्पणी करना कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह विधि सम्मत है क्योंकि खजुराहो परिसर में केवल एक मन्दिर को छोड़ कर जितने भी मन्दिर हैं उनमें लगी या स्थापित किसी भी देव प्रतिमा की पूजा नहीं होती है क्योंकि ये प्रायः खंडित है और सनातन धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। इसके साथ ही यह पूरा क्षेत्र भारतीय पुरातत्व विभाग के नियन्त्रण में है और विश्व धरोहरों में शुमार किया जाता है। जाहिर है कि राकेश किशोर ने एक वकील होते हुए संविधान को शर्मसार करने वाला ऐसा घृणित कार्य केवल सस्ती लोकप्रियता व चर्चा पाने की गरज से ही किया जिसके राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं। अतः भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि वकील राकेश किशोर की बात पर जरा भी ध्यान न दें और समाज में शान्ति बनाये रखें क्योंकि यह समूची न्यायप्रणाली पर हमला है।

बिहार में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा

कमलेश पांडे ।

लोकतंत्र की जननी बिहार के राजनेतागण अपनी व्यक्तिगत, गुटगत, पार्टीगत और गठबंधनगत सियासी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए चुनावी जनादेश को अक्सर धता बताने के आदी समझे जाते है। पहले जब यहां कांग्रेस का एकछत्र राज या जनता पार्टी-जनता दल का छिटपुट राज हुआ करता था, तब मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे। लेकिन जब क्षेत्रीय दलों के रहनुमा लालू प्रसाद (राजद) या नीतीश कुमार (जदयू) की सियासी चलती आई तो मुख्यमंत्री कम, गठबंधन साथी बदलने की एक नई परिपाटी शुरू हो गई। लोजपा नेता स्व. रामविलास पासवान और अब उनके पुत्र केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हम नेता व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी पार्टी नेता मुकेश सहनी के अलावा वामपंथी दलों ने इनका खूब साथ दिया। बताया जाता है कि इसके पीछे कांग्रेस और भाजपा के केंद्रीय व सूबाई नेतृत्व की अदूरदर्शिता भरी मनमानी तथा राजद और जदयू आदि क्षेत्रीय दलों के घात-प्रतिघात की सियासत की भी बड़ी भूमिका रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि टीम मोदी इसबार इन राजनीतिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी तो केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को सभी चुनावों की मां बताया है। क्योंकि समझा जा रहा है कि यह इलेक्शन कई कारणों से बिहार की सियासत को बिल्कुल नया रंग देने वाला है। यह ठीक है कि पिछले दो दशकों से एनडीए ने बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को मुख्य केंद्रीय भूमिका में बनाए रखा है और भाजपा को इसकी भारी चुनावी कीमत भी चुकानी पड़ी है। शायद इसलिए कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और विगत तीन-साढ़े तीन दशकों उसके चहेते नेता लालू प्रसाद (राजद) व उनके पुत्र व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सूबाई सत्ता से दूर रखा जा सके। कहा जाता है कि बिहार में लालू प्रसाद के सियासी कुनबे को स्थापित देने, दिलवाने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए भाजपा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभी मनमानियों को बर्दाश्त करते हुए उन्हें अपने पाले में मिलाए रखती है। दो दो बार नीतीश कुमार भाजपा से दूर भी गए, लेकिन उन्हें निकट लाने का कोई भी मौका भाजपा ने नहीं गंवाया। फिलवक्त यह चर्चा है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के जीवन का शायद आखिरी इलेक्शन हो सकता है। चूंकि बिहार की महिलाओं और एमबीसी मतदाताओं पर नीतीश कुमार की शुरू से पकड़ रही है, इसलिए इस बार महिलाओं और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता की परीक्षा होगी। वैसे तो सवर्णों और अल्पसंख्यकों को भी मुगालते में रखने में वो सफल रहे है, लेकिन इस बार की सियासी स्थिति काफी बदल चुकी है। कई ऐसे सियासी प्रसंग छिड़े, जिनसे नीतीश कुमार बेनकाब हो चुके हैं। यह ठीक है कि गठबंधन में बार-बार बदलाव करके नीतीश कुमार राजनीतिक समीकरण के केंद्र में बने रहे। लेकिन, इस बार उनके सामने अपने विधायकों के खिलाफ बढ़ती नाराजगी, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप और राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की मजबूत चुनौती उनके समक्ष है। जदयू नेता नीतीश कुमार को यह याद है कि 2020 में लोजपा नेता चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिससे जदयू की सीटें भाजपा के मुकाबले काफी कम होकर महज 43 तक सिमट गईं। लेकिन इस बार एनडीए के लिए राहत की बात यह है कि चिराग पासवान की लोजपा (राम विलास) गठबंधन में बनी हुई है और साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इससे एनडीए को चिराग के 5 प्रतिशत पासवान वोट आधार के अलावा दलित मतों पर भरोसा है, जो कि इस चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं, एनडीए के पूर्व सहयोगी वीआईपी नेता मुकेश सहनी,जो 2020 में एनडीए के साथ रहकर चार सीटें जीते थे, इस बार वह इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। इससे गंगापुत्र वोटों की क्षति भाजपा को उठानी पड़ सकती है। वैसे महागठबंधन में सीट बंटवारे पर वीआईपी पार्टी की भी बातचीत चल रही है। इससे इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि सहनी के निषाद समुदाय का समर्थन मिलेगा, जो मिथिलांचल, सीमांचल, अंग और चंपारण में अहम वोटर समझे जाते हैं। यह उनकी जीत में मदद करेगा। शायद यह बिहार में पहला ऐसा चुनाव है जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मुफ्त योजनाओं की झड़ी लगा दी और नकद धनराशि देने पर भी जोर दिया है। यह उनकी सामान्य रणनीति से अलग है। यही वजह है कि गत सोमवार को आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले नीतीश ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपये भेजे। इस प्रकार से कुल मिलाकर राज्य सरकार ने 1.21 करोड़ महिलाओं को 12,100 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। वहीं, अगले 29 लाख लाभार्थियों के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। हालांकि, आगे के हस्तांतरण के लिए निर्वाचन आयोग की मंजूरी जरूरी होगी। इसके अलावा, पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये प्रति माह किया गया है। वहीं, कई सरकारी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। यह सब नीतीश कुमार ने इसलिए किया ताकि विरोधियों को सियासी शिकस्त दी जा सके। हालांकि, सवर्णों के वोट आधार पर अपनी-अपनी सियासत चमकाने वाली जदयू-भाजपा को इस बार जनसुराज पार्टी के संस्थापक व मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के रूप में एक नई चुनौती मिल रही है, जो तेजस्वी यादव से ज्यादा खतरनाक है। ऐसा इसलिए कि कई वर्षों बाद बिहार में एक ऐसा नया चेहरा चर्चा में है जो सवर्ण पृष्ठभूमि का है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पिछले तीन वर्षों से राज्य में प्रचार कर रहे है और उनकी ओर से लगाए गए सरकारी भ्रष्टाचार के आरोप पूरे राज्य में चर्चा का विषय बने हुए है। इससे सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन दोनों सतर्क हो गए हैं। हालांकि, अभी यह देखना बाकी है कि क्या वह इन चर्चाओं को वोटों में बदल पाएंगे। इस तरह 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव न केवल नीतीश कुमार की विरासत की परीक्षा लेगा, बल्कि भाजपा के नए चेहरों और विपक्ष की बदलती रणनीतियों के साथ सियासत को नया आयाम भी देगा। इसलिए बिहार में चुनाव को प्रभावित करने वाले कतिपय महत्वपूर्ण व प्रमुख फैक्टर्स का विश्लेषण करना लाजिमी है, जो यह निर्धारित कर सकते हैं कि सत्तारूढ़ एनडीए सत्ता में बनी रहेगी या फिर जनता विपक्षी गठबंधन को समर्थन देकर आश्चर्यचकित कर देगा, या फिर 2025 की तरह ही एक बार फिर त्रिशंकु सरकार बनेगी। बिहार में चुनावी बिगुल आधिकारिक तौर पर बज चुका है। चुनाव आयोग द्वारा 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में वोटिंग के ऐलान के साथ, एक बेहद अहम राजनीतिक मुकाबले का मंच तैयार है। लेकिन इस अहम मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है? 14 नवंबर को नतीजों का इंतज़ार रहेगा। यूँ तो तमाम चुनाव पूर्व आए मतदाता सर्वेक्षण में एनडीए के लिए अंकगणितीय बढ़त की बात बताई जा रही है, लेकिन कागजों पर और सियासी जमीन पर यह गणनात्मक दौड़ कितनी सही बैठी, इसका खुलासा 14 नवम्बर को ही हो पाएगा। यह ठीक है कि राजनीतिक अंकगणित के आधार पर एनडीए की स्पष्ट बढ़त से चर्चा शुरू होती है, लेकिन विपक्ष को हल्के में लेना उनकी बड़ी भूल साबित हो सकती है। यह ठीक है कि सत्तारूढ़ एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा आदि शामिल है। इसलिए यह गठबंधन संख्याबल के रूप से विपक्ष यानी आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के गुट से ज्यादा मजबूत प्रतीत है, वो भी तब जब सवर्ण व मुस्लिम वोटों का बंटवारा न हो।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भले ही आंकड़ों का गणित एनडीए के पक्ष में हो सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर बिखरे हुए राजनीतिक समीकरण मुकाबले को और अधिक दिलचस्प बना देते है। ज्यादातर सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए पसंदीदा विकल्प हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती उनका पारिवारिक कलह है। वहीं, आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम-यादव (एम-वाई) वोट आधार से आगे खासकर सवर्णों के बीच उनकी अपनी अपील का विस्तार करना है, जिससे मुकाबला रोचक हो सकता है। इसी बीच काबिलेगौर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल की सत्ता-विरोधी लहर से जूझ रहे हैं और मोदी-शाह के बढ़ते दबाव के चलते कुछ लोग उन्हें हाल के वर्षों में एक कमजोर नेता के रूप में देखते हैं। इससे वे अपनी पार्टी के लिए एक संपत्ति और एक बोझ दोनों बन चुके है। हालांकि एकमुखी दल के लिए यह आम बात है। वे एक सियासी सम्पत्ति इसलिए हैं क्योंकि उन्हें करीब 15 प्रतिशत वोट शेयर लगातार मिलता आया है। और एक बोझ इसलिए भी है क्योंकि वे सत्ता-विरोधी लहर का चेहरा है। दो दो बार तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री उन्होंने बनवाया है, इसलिए उनपर लोगों का भरोसा करना कठिन हो जाता है। लिहाजा, अहम सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अपनी सियासी जमीन बचा पाएंगे या अब उनका स्थायी पतन हो रहा है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के सुनहरे सपने भी ध्वस्त हो जाएंगे। क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और 2027 में उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव पर बिहार के जनादेश का सीधा असर पड़ेगा। इसबार के चुनाव की खास बात यह भी है कि कल्याणकारी योजनाएं बनाम सत्ता-विरोधी भावना का लिटमस टेस्ट यहां होना है। यूँ तो फॉर्मूले से कई नई सरकारें बन चुकी हैं और पुरानी सरकारें भी बची है। इसलिए एनडीए ने बिहार में भी फॉर्मूले के प्रयोग को दोहरा दिया है।

जी.एस.टी. रिफंड में देरी : पंजाब की इंडस्ट्री पर 'कैश फ्लो' संकट

हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) की स्लैब्स में हुए बड़े बदलाव से 12 व 28 प्रतिशत दरों को हटाकर इन्हें 5 व 18 प्रतिशत में मिला दिया गया। बेशक कई औद्योगिक सैक्टरों के लिए यह बदलाव एक बड़ा सुधार है लेकिन कारोबार को आसान व टैक्सेशन सिस्टम में पारदर्शिता की दिशा में इस अहम कदम का दावा उन इंडस्ट्रीज के लिए बेमानी है, जो 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' (आई.डी.एस.) के दायरे में है, यानी जिनके कच्चे माल पर अधिक टैक्स, जबकि तैयार माल पर कम टैक्स लगता है। पंजाब के औद्योगिक सैक्टर की रीढ़ कृषि उपकरण, ट्रैक्टर और उनसे जुड़ी अन्य इंडस्ट्रीज के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से एक गंभीर कैश फ्लो (नकदी प्रवाह) संकट राज्य के औद्योगिक सैक्टर को आगे बढ़ने की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फंसे उद्योग – इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में इंडस्ट्रीज अपने कच्चे माल जैसे स्टील, रबड़, प्लास्टिक व अन्य जरूरी इनपुट पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. दे रही है, जबकि उनके तैयार माल जैसे ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरणों पर 5 प्रतिशत जी.एस.टी. लगता है। जी.एस.टी. एक्ट के तहत एक तय समय पर रिफंड न होने की वजह से टैक्स न्यूट्रैलिटी (कर निष्पक्षता) सिद्धांत के कोई मायने नहीं रह जाते। टैक्स न्यूट्रैलिटी के बावजूद पंजाब में इनपुट टैक्स क्रैडिट (आई.टी.सी.) रिफंड में 6 महीने से 1 साल की देरी के कारण इंडस्ट्री का 'वर्किंग कैपिटल' अटकने से उत्पादन, रिसर्च एवं इनोवेशन व एक्सपैंशन प्रभावित हो रहा है। पहला, लिक्विडिटी संकट से कंपनियों को रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए महंगी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ रहा है। दूसरा, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आने वाले पंजाब के उद्योग अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ सकते हैं। रिफंड में देरी पंजाब के जी.एस.टी. प्रशासन की पुरानी समस्या रही है लेकिन स्लैब बदलने के बाद यह समस्या और गहरी हो गई है। अगर समय रहते कदम न उठाए गए, तो नकदी की यह किल्लत पंजाब में 'इंडस्ट्रीयल स्लो डाऊन' यानी औद्योगिक सुस्ती का एक बड़ा कारण बन सकती है। देरी की गुंजाइश नहीं : 'ईज ऑफ डूइंग बिजनैस' यानी कारोबार को आसान करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान व उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की कारोबारियों से लगातार बातचीत से प्रदेश में नया निवेश आकर्षित करने व मौजूदा उद्योगों को संकट से उबारने की उम्मीदें जुड़ी है। अगर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत उद्योगों की समस्या हल नहीं हुई, तो बाकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हो सकती है। समय पर इनपुट टैक्स क्रैडिट रिफंड कानूनी अधिकार है, कोई इंसेंटिव नहीं। राज्य की अर्थव्यवस्था व रोजगार के अवसर बढ़ने के लिए इंडस्ट्री से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह लंबे समय तक रिफंड का इंतजार करे। कारोबार में सहजता सबसे बड़ी प्राथमिकता : असल समस्या केवल रिफंड की नहीं, बल्कि भरोसे की है। कारोबारी किसी राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनैस को सिर्फ कागजी योजनाओं से नहीं, बल्कि हकीकत में उनके लागू होने की विश्वसनीयता से परखते हैं। अगर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली इंडस्ट्री को लगातार कैश फ्लो ब्लॉकेज झेलना पड़ा, तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। जी.एस.टी. स्लैब्स में सुधार के बाद पंजाब के पास सही दिशा में कदम बढ़ाने का यह सबसे अच्छा मौका है। समय पर रिफंड सुनिश्चित करके सरकार न सिर्फ उद्योगों को नकदी के संकट से बचा सकती है, बल्कि औद्योगिक प्रशासन की विश्वसनीयता में और मजबूती कायम की जा सकती है। पंजाब जो भारत का 'अन्न भंडार' है व औद्योगिक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, के लिए कारोबार में सहजता सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

रिफंड में तेजी का रोडमैप : केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 1 नवम्बर से कारोबारियों द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी करने के 1 हफ्ते के भीतर रिफंड सुनिश्चित किया जाएगा। पंजाब को भी इसी दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। एक ठोस रोडमैप लागू करने के लिए तीन अहम कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, समयबद्ध रिफंड सिस्टम, पंजाब को भी 10-15 दिन की समय-सीमा तय करनी चाहिए और अगर इस दौरान कोई आपत्ति न हो तो रिफंड अपने आप मंजूर हो। 30 दिन से ज्यादा की देरी पर जी.एस.टी. प्रशासन कारोबारियों को ब्याज का भुगतान करे। दूसरा, डिजिटल-फर्स्ट प्रोसैसिंग। पंजाब एक 'ऑटो-वैलिडेशन' सिस्टम ला सकता है, जिसमें इनपुट जी.एस.टी. क्रैडिट और आऊटपुट के बीच के अंतर का अपने आप जी.एस.टी.-एन सिस्टम से मिलान हो जाए। इसके अलावा एक विशेष हैल्प डैस्क बनाया जाए, जो सिर्फ इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड से जुड़ी शिकायतों का निपटान करे। तीसरा, केंद्र-राज्य सरकार में तालमेल। चूंकि जी.एस.टी. कलैक्शन केंद्र सरकार के खाते में जाता है, ऐसे में पंजाब को समय पर जी.एस.टी. फंड एडजस्ट कराने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय से तालमेल बैठाना होगा। इधर राज्य के वित्त विभाग, जी.एस.टी. प्रशासन और उद्योग विभाग की एक ज्वाइंट वर्किंग कमेटी बनाकर रिफंड के लंबित मामलों का तुरंत निपटान किया जा सकता है।

आगे की राह: इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत इंडस्ट्रीज को समय पर इनपुट टैक्स क्रैडिट रिफंड टैक्सेशन सुशासन की बुनियादी शर्त है। इसे कारगर ढंग से लागू करके पंजाब अपनी औद्योगिक ताकत को और बढ़ा पाएगा।

भारतीयों के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं

जैसे किसी युद्ध के मैदान में लगातार बमों की बारिश होती है, कुछ इसी तरह से इन दिनों अमरीका द्वारा भारत पर लगातार 'बम' गिराए जा रहे हैं। कभी 50 प्रतिशत का टैरिफ बम, कभी दवाओं और फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ, तो कभी एच-1 वीजा पर 88 लाख रुपए की मोटी फीस। यह वही अमरीका है, जिसने ग्लोबलाइजेशन के दौर में कहना शुरू किया था कि व्यापार का कोई देश नहीं होता। जहां मुनाफा,वहीं व्यापार। इसीलिए तमाम बहुराष्ट्रीय निगम चीन और अन्य देशों की तरफ दौड़े थे, क्योंकि वहां अमरीका की तरह कठोर श्रम कानून नहीं हैं। इसके अलावा अमरीका में जो तनख्वाहें है, उसके मुकाबले इन देशों में बहुत कम देकर काम कराए जा सकते हैं। चीन का उभार इसी तरह से हुआ। हेनरी किसिंजर ने चीन की यात्रा की थी और व्यापार का रास्ता प्रशस्त किया था। चीन ने न केवल अमरीका बल्कि दुनिया भर के बाजारों को अपने यहां बने सस्ते सामानों से पाट दिया। आज चीन दुनिया की दूसरे नम्बर की आर्थिकी है। अमरीका उसे चुनौती की तरह देख रहा था। दूसरी तरफ उसे मैक्सिको से बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासियों से शिकायत थी। तीसरी बात अमरीका में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं को रोकना था। लेकिन हुआ क्या। राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के बाद पहला हमला भारतीयों पर बोला गया। पिछले दिनों एक ऑनलाइन 'हेट कैम्पेन' चलाई गई जिसमें इन्हें जॉब थीव्स (रोजगार चुराने वाले) और इनवेडर्स (आक्रांता) कहा जा रहा है। क्या सचमुच ऐसा है? भारतीयों ने सिलिकान वैली को बनाया है। तमाम बड़े उद्योगपतियों के यहां काम करके, उन्हें कहीं से कहीं पहुंचा दिया। सबसे दुखद यह है कि इस तरह की कैम्पेन को परोक्ष-अपरोक्ष रूप से सरकार का समर्थन प्राप्त है। कोई सरकार इस तरह किसी कम्युनिटी के खिलाफ कैम्पेन में सहभागी हो तो उन लोगों की हिम्मत बढ़ना तय है जो इस बहाने भारतीयों पर हमले कर रहे हैं। इस प्रसंग में युगांडा के ईदी अमीन की याद आती है। उन्होंने भी कभी भारतीयों को इसी तरह से खदेड़ा था। जबकि दुनिया भर में भारतीय जहां रहते है वे बेहद मेहनती और अपने काम से काम रखने वाले माने जाते हैं। यही कारण है कि मशहूर उद्योगपति बिल गेटस ने कहा कि अगर हम भारतीयों की सेवा लेना बंद कर देंगे तो वे अपना माइक्रोसाफ्ट बना लेंगे। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी कहा कि हमारी कम्पनी बनाने में भारतीयों का भारी योगदान है। कई अन्य लोगों ने कहा कि हमें भारतीय इंजीनियर्स की जरूरत है। सबसे ज्यादा दिलचस्प यह है कि जिन भारतीयों को अमरीका के एक सबसे बड़े नेता द्वारा लगातार पीटा जा रहा है, उन्होंने उसे बड़ी संख्या में वोट दिए हैं। उन्हें क्या पता था कि इसकी तपिश उन्हें ही झेलनी पड़ेगी। यही नहीं, जिस पाकिस्तान को कल तक अमरीका आतंकवाद को शरण देने के कारण कोस रहा था, उसे ही बार-बार गले लगाया जा रहा है। पाक सेनाध्यक्ष की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। हाल ही में कहा गया कि असीम मुनीर को पसंद करने की वजह यह है कि उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने बन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08862)

हरिओम बाल्मीकि की न्यायिक लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस-प्रदीप नरवाल

दलित उत्पीड़न में भाजपा ने की हदें पार-नीलांसु चतुर्वेदी

फतेहपुर।

दलित युवक हरिओम बाल्मीकि की हत्या को लेकर गंभीरकांग्रेस पार्टी नेताओं के निरंतर आगमन के क्रम में आज राष्ट्रीय सचिव एवं बुंदेलखंड प्रभारी नीलांसु चतुर्वेदी एवं राष्ट्रीय सचिव एवं पश्चिम जोन प्रभारी प्रदीप नरवाल पीड़ित के घर पहुंच कर परिजनों से मुलाकात की। श्री नरवाल ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस घटना की पूरी न्यायिक लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस दोषियों को कठोर दंड दिलाकर दम लेगी। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरे देश में दलित समाज को टारगेट कर उत्पीड़न किया जा रहा है जिसका कांग्रेस कड़ा विरोध करते हुए अंतिम लड़ाई तक डटी रहेगी। वही राष्ट्रीय सचिव नीलांसु चतुर्वेदी ने कहा कि आज देश में उत्तर प्रदेश एक आपराधिक प्रदेश बन कर रह गया है जिसमें सब से ज्यादा दलित उत्पीड़न हुआ है, आज अपराधी निडर होकर कानून अपने हाथ में लेकर निरंकुश अपराध कर रहा है जो बहुत दुखद पहलू है साथ ही उन्होंने जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी व शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा को निर्देश दिया कि पीड़ित परिजनों से बराबर संपर्क में रहते हुए हर संभव मदद करें। राष्ट्रीय नेताओं के साथ पहुंचे शेख एजाज अहमद,कलीम उल्ला सिद्दीकी, शिवा कांत तिवारी,देवी प्रकाश दुबे, माधुरी रावत, ओम प्रकाश गिहार,बसीर अहमद, सैयद सहाब अली, आदित्य श्रीवास्तव, मोहसिन खान, डॉ अब्दुल हमीद,कौशल कुमार शुक्ला, अजय बच्चा, शकीला बानो, इशरत खान, निजामुद्दीन, मिस्बाहुल हक, उस्मान बेग, चौधरी मोइन राइन, आदि कांग्रेसी मौजूद रहे।

गेंद घर मैदान में नौ अक्टूबर को स्वदेशी मेले का होगा भव्य शुभारम्भ

बहराइच। इण्डिया एक्सपो सेन्टर-मार्ट ग्रेटर नोयडा में आयोजित यू.पी.आई.टी.एस. की भाँति यू.पी. इन्टरनेशनल ट्रेड शो-2025 के अन्तर्गत गेंद घर मैदान में 09 से 18 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले स्वदेशी मेले के सफल आयोजन हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र ने बताया कि मेले आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि दिवाली महापर्व के अवसर पर हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों द्वारा स्थानीय स्तर पर उत्पादित किये जा रहे उत्पादों (स्वदेशी वस्तुओं) की खरीदारी का आमजनमानस को अवसर प्राप्त हो सके। सीडीओ श्री चन्द्र ने उप निदेशक कृषि, उद्यान अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, परियोजना अधिकारी डूडा, लीड बैंक प्रबन्धक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सहित व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि दीवाली महापर्व के अवसर पर पब्लिक डिमाण्ड के अनुसार स्टालों की स्थापना करायें तथा आयोजन को रूचि पूर्ण बनाये जाने हेतु महिलाओ एवं बच्चों के मनोरंजन तथा खान-पान के लिए पर्याप्त संख्या में स्टालों की व्यवस्था की जाय। सीडीओ श्री चन्द्र ने जनपद के व्यवसायियों एवं व्यापारियों का आहवान किया कि इस अवसर का भरपूर लाभ उठाते हुए स्वदेशी मेले में हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों द्वारा स्थानीय स्तर पर उत्पादित किये जा रहे उत्पादों के स्टाल लगाये।

सीडीओ श्री चन्द्र ने बताया कि 09 अक्टूबर 2025 को अपरान्ह 04:00 बजे स्वदेशी मेले का शुभारम्भ होगा। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग केशव राम वर्मा, एलडीएम जितेन्द्र मसन्द, उप निदेशक कृषि विनय कुमार वर्मा, अधि.अधि. न.पा.परि. बहराइच प्रमिता सिंह, सहायक निदेशक रेशम मिथलेश सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

दीपावली पर स्थानीय उत्पादों को दें प्राथमिकता: डीएम

मुरादाबाद। शहरी क्षेत्र में सक्रिय स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के दृष्टिगत जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि दीपावली पर्व के दौरान स्थानीय स्तर पर तैयार कराए गए उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करके हस्तशिल्पियों और कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के संबंध में शासन स्तर से निर्देश हैं। शहरी क्षेत्र में दिए, झालर, मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि तैयार करने वाले स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न कार्यालय परिसरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्टॉल स्थापित करने का अवसर दिया जाएगा ताकि यह समूह अपने उत्पादों की बिक्री कर सके तथा आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त बन सके। बैठक में एसडीएम सदर, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही चिन्हित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भी मौजूद रहीं।

बैठक में एसडीएम सदर, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही चिन्हित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भी मौजूद रहीं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ राम लीला महोत्सव का हुआ समापन

वायलेंट द म्यूजिकल बैंड एवं इंडियन आइडल के कलाकारों ने दी प्रस्तुति

बहराइच।

श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लीला कमेटी के तत्वावधान में 14 दिवसीय राम लीला महोत्सव का सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। 22 सितम्बर से शुरू हुए महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए।सांस्कृतिक कार्यक्रम में इंडियन आइडल के कलाकार कुलदीप सिंह चौहान ने भक्ति,बॉलीवुड गीत संगीत से जलवा बिखेरा।कार्यक्रम की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष श्याम करण टेकड़ीवाल ने की। राम लीला महोत्सव समापन कार्यक्रम के अंतर्गत वायलेंट द म्यूजिकल बैंड द्वारा शहर के घन्टाघर पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में इंडियन आइडल के चर्चित कलाकार कुलदीप सिंह चौहान सहित अन्य कलाकारों ने भक्ति गीत संगीत से कार्यक्रम में समा बांधा।श्रोताओं ने देर रात तक गीत संगीत का लुत्फ उठाया।सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 14 दिवसीय राम लीला महोत्सव का समापन हो गया।कार्यक्रम में राम लीला महोत्सव में योगदान देने वाले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह,कमेटी अध्यक्ष श्याम करण टेकड़ीवाल, विभाग प्रचारक कृष्ण कुमार,जिला प्रचारक अजय,विधायक प्रतिनिधि अशोक जायसवाल,भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेश पाण्डेय,संतोष अग्रवाल,जितेन्द्र अग्रवाल,राहुल रॉय, कमल शेखर गुप्ता,राकेश मित्तल,राज कमल गुप्ता,देवकुमार रस्तोगी,मीडिया प्रभारी सचिन श्रीवास्तव,नन्हे लाल लोधी,विनय जैन,सुरेश गुप्ता,आनंद गुप्ता, के के सक्सेना,अंशुमान यज्ञसैनी,सुशील कुमार,एस पी मिश्रा,पुष्प नाथ तिवारी,मनोज मिर्ची,अजय सिंह,मनोज गुप्ता,वासु साहू,राहुल दीक्षित,के के मिश्रा,अशोक सैनी,सिद्धार्थ सिंह,हर्षित राज श्रीवास्तव,जगदम्बा सोनी,निशा शर्मा,एकता जायसवाल सहित अन्य राम भक्त मौजूद रहे।

बच्चियों को वितरित किये उपहार, खिलाई मिठाई

मुरादाबाद। मिशन शक्ति के अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय सोनकपुर बिलारी में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केक काटकर किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चियों को उपहार और मिठाई वितरित की गई। इस दौरान महिला कल्याण सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), वन स्टॉप सेंटर तथा चाइल्डलाइन की कार्य प्रणाली और उनसे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और आपातकालीन सेवा 112 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। बच्चियों को विस्तारपूर्वक बताया गया कि कैसे इस नंबरों के द्वारा सहायता ले सकती हैं। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर से मनोसामाजिक परामर्शदाता तनीषा दिवाकर, केस वर्कर युक्ति पांडे, अंशु चतुर्वेदी होमगार्ड, अध्यापक, अध्यापिका ,छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे।

भाजपा के प्रति तेजी से बढ़ रहा जनता का विश्वास: रामवीर सिंह

मुरादाबाद।

भाजपा मूंढापांडे एवं दलपतपुर मंडल की बैठक महर्षि दयानंद लॉ कॉलेज भदासना एवं आर्केडिया ग्रीन्स में आयोजित की गई। बैठक में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में सभी शक्ति केंद्र संयोजक एवं शक्ति केंद्र प्रभारी शामिल हुए। बैठक में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र, मंडल और बूथ के बीच समन्वय जरूरी है। शक्ति केंद्र की सक्रियता से मंडल और बूथ स्वतः सक्रिय होंगे। उन्होंने विपक्ष के भ्रम और अफवाहों का जनसंवाद से मुकाबला करने की रणनीति बताई। बूथ के प्राथमिक और सक्रिय सदस्यों से संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। युवाओं को संगठन में जिम्मेदारी देकर नए कार्यकर्ता तैयार करने की बात कही। भाजपा का मूल आधार कार्यकर्ता हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता ही पार्टी की असली शक्ति है और संगठन को गांव-गांव, घर-घर तक ले जाने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि आज देश और राज्य में भाजपा के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हमें अपने व्यवहार, मेहनत और सेवा भाव से उस विश्वास को और मजबूत करना होगा। चुनावों को बगैर ध्यान में रखते हुए संगठित होकर सक्रिय रूप से जनता के बीच काम करने का आह्वान किया। बैठक में उपस्थित शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारी ने एकजुट होकर संगठन को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष दलपतपुर नीरज चंद्रा, मंडल अध्यक्ष मुंढापांडे महेंद्र सैनी, अशोक प्रजापति, वीरपाल प्रजापति, परशुराम सैनी, देवीलाल प्रजापति, नंदराम सैनी, सोनू सैनी, राजेंद्र कश्यप, मीना सैनी, महिपाल, डॉ प्रमोद यादव, विपिन जाटव, रजनीश चौहान, गौरव, इंद्रपाल, खेमपाल सिंह, आयुष प्रताप, अंकित, एहसान अली, अनीस आदि उपस्थित रहे।

पराली प्रबंधन की जागरुकता को रवाना किया प्रचार वाहन

मुरादाबाद।

जिलाधिकारी अनुज सिंह एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ममता मालवीय तथा सन्तोष कुमार द्विवेदी उप कृषि निदेशक द्वारा पराली प्रबंधन की जागरुकता हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया गया। प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इनसीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेजीड्यू योजनान्तर्गत धानकी पुआल /गन्ने की पत्तियां/ फसल अवशेष को न जलाने एवं सड़ाकर खाद बनाये जाने हेतु कृषकों को जागरुक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा उक्त प्रचार वाहन को प्रत्येक विकास खंडों मे चलाया जायेगा तथा कृषकों को जागरुक किया जायेगा। सन्तोष कुमार द्विवेदी उप कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी के आदेश से राजस्व विभाग ,कृषि विभाग ,पुलिस विभाग की सयुक्त निगरानी टीम पराली प्रबंधन हेतु जनपद स्तर तहसील स्तर एवं विकास खंड स्तर पर बनाया गया है। पराली जलाये जाने की सैटेलाईट के माध्यम से सूचना प्रति दिन प्राप्त होती है ,जिसमे अक्षांश ,देशान्तर के साथ स्थल दिया रहता है,जिसके आधार पर कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी स्थलीय निरीक्षण करके आख्या देते है। पराली जलाये जाने पर 02 एकड तक रु5000/ ,02 से 05 एकड तक रु10000/ तथा 05 एकड से अधिक होने पर रु. 30000/ का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान है तथा कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है। उप कृषि निदेशक, मुरादाबाद द्वारा कृषकों से अनुरोध किया गया है कि वे फसल अवशेष कदापि न जलायें तथा उसे सड़ाकर खाद बनायें।

अमित शाह पर ममता का बड़ा आरोप -कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह कर रहे बर्ताव, मोदी रहें सावधान

बंगाल।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरकतें कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसी हैं। बाढ़ से तबाह उत्तरी बंगाल से लौटने के बाद कोलकाता हवाई अड्डे के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, बनर्जी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहती हैं कि वे शाह पर ज्यादा भरोसा न करें, जो एक दिन उनके मीर जफ़र बन सकते हैं, बंगाल के 18वीं सदी के सैन्य जनरल जिन्होंने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और बाद में अंग्रेजों की मदद से राजा बने थे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लागू करने के नाम पर चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है, वह शाह के इशारे पर कर रहा है, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, प्रधानमंत्री को उनके सभी कार्यों की जानकारी है। ममता बनर्जी ने कहा कि आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा में क्या हो रहा है। हमारे मंत्रियों, सांसदों और विधायकों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वहाँ भेजा गया था। लेकिन उन्हें हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। यहाँ तक कि उनकी टैक्सी को भी आने की अनुमति नहीं है, उन्हें आने से मना किया गया। उन्होंने दावा किया कि मैंने उन्हें पैदल (अगरतला टीएमसी कार्यालय तक) जाने को कहा, उन्होंने बाइक से जाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी अनुमति नहीं दी गई। अगर उन्हें पैदल भी जाने की अनुमति नहीं है, तो मैं खुद वहाँ जाऊँगी। हम उनका दुस्साहस भी देखेंगे... त्रिपुरा में आपकी डबल इंजन वाली सरकार है। सबसे पहले, अभिषेक बनर्जी के वाहन में तोड़फोड़ की गई। उस समय आपकी सारी सलाह कहाँ थी? जब डोला सेन के वाहन पर हमला हुआ, सुष्मिता देव के वाहन पर हमला हुआ, सांसदों के वाहन पर हमला हुआ, पत्रकारों के वाहन पर हमला हुआ, क्या डबल इंजन वाली सरकार को माफ़ किया गया? वे टीएमसी के बारे में झूठ बोलते हैं और हिंसा का समर्थन करते हैं।

बाढ़ से तबाह उत्तरी बंगाल से लौटने के बाद कोलकाता हवाई अड्डे के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, बनर्जी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहती हैं कि वे शाह पर ज़्यादा भरोसा न करें, जो एक दिन उनके मीर ज़फ़र बन सकते हैं, बंगाल के 18वीं सदी के सैन्य जनरल जिन्होंने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और बाद में अंग्रेजों की मदद से राजा बने थे।

बरेली बवाल: कानूनी चक्रव्यूह में फंसा मौलाना तौकीर, दस मुकदमों में होगी तलबी

बरेली फतेहगढ़ जेल में बंद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां कानूनी दांवपेंच के चक्रव्यूह में फंस गया है। फिलहाल उसका जेल से निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। कोतवाली के अलावा बवाल के दिन दर्ज नौ अन्य मुकदमों में साजिशकर्ता के रूप में तौकीर को नामजद किया गया है। इन मुकदमों के विवेचकों ने तौकीर का वारंट बी फतेहगढ़ जेल में दाखिल किया है। मौलाना की तलबी 14 अक्तूबर को की जानी है। दंगा कराने में 2010 से मौलाना तौकीर का नाम कई बार उछलता रहा है, लेकिन मौलाना पर कभी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। कभी सत्ताधारियों का करीबी होने का मौलाना को फायदा मिला तो कभी सरकारों ने दरगाह परिवार से जुड़ाव के मद्देनजर तौकीर को रियायत बख्श दी। इस बार 26 सितंबर को प्रदर्शन का आह्वान करके मौलाना तौकीर ने मुसीबत मोल ले ली। मौलाना फतेहगढ़ जेल में और उसके खास गुर्गे बरेली जेल में बंद हैं। 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के बाद पुलिस ने पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें से कोतवाली के पांच मुकदमों समेत सात में मौलाना

तौकीर का नाम शामिल था। चूंकि आयोजन तौकीर रजा के ही बुलावे पर होना था, इसलिए बाकी मामलों में भी साजिशकर्ता के तौर पर तौकीर का नाम जोड़ा गया है। इस तरह हालिया नौ मुकदमों में तौकीर को आरोपी बनाया गया है। इन नौ मामलों में बी वारंट फतेहगढ़ जेल में दाखिल किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2019 में सीएए एनआरसी मामले में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का मामला अभी तक कोतवाली में प्रचलित था, इसके विवेचक ने भी मौलाना को अपने मामले में आरोपी बताकर बी वारंट दाखिल किया है। शुरू में सात मामलों में मौलाना को तलब कराने के लिए बी वारंट दाखिल किया गया था। इसके लिए सोमवार को सुनवाई होनी थी। बताते है कि फतेहगढ़ जेल प्रशासन ने स्टाफ की कमी की मजबूरी जताई तो सुनवाई टल गई। अब 14 अक्तूबर की तारीख सुनवाई के लिए लगी है। तौकीर को इस दिन फतेहगढ़ जेल से लाकर बरेली कोर्ट में पेश किया जा सकता है। चूंकि जल्द ही दीपावली है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होने के आसार ज्यादा हैं। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा से संबंधित सभी मुकदमों में विवेचना से लेकर गिरफ्तारी तक उच्च अधिकारियों की देखरेख में चल रही है। निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जा रही है। मौलाना तौकीर रजा 27 सितंबर से फतेहगढ़ सेंट्रल जेल की तन्हाई बैरक में बंद है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी शासन स्तर से की जा रही है। मौलाना की गतिविधियों से लेकर उससे मुलाकात करने वालों तक का पूरा ब्योरा अपडेट रखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेल प्रशासन ने मौलाना को ज्ञानवर्धक पुस्तकें मुहैया कराई हैं। उसे इच्छा के मुताबिक हिंदी व उर्दू साहित्य की पुस्तकें दी जा रही हैं।

हमारे सांसद पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया
खगेन मुर्मू से मिलने के बाद सरकार पर बरसे सुकांत मजूमदार

कोलकाता केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने सिलीगुड़ी में भाजपा सांसद खगेन मुर्मु और विधायक शंकर घोष से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। बता दें कि, सांसद खगेन मुर्मु पर कथित तौर पर कुछ स्थानीय लोगों ने हमला किया था, जब वह 6 अक्तूबर को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के दुआर्स क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा ले रहे थे। इस दौरान उनके सिर और आंख के पास गंभीर चोटें आईं। इस घटना के दौरान उनके साथ विधायक शंकर घोष भी थे, उन्हें भी चोट लगी है, उन्होंने आरोप लगाया कि राहत सामग्री वितरित करते समय उन पर हमला किया गया। दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद प्रेस से बात करते हुए सुकांत मजूमदार ने बताया कि शंकर घोष की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है क्योंकि उनके कंधे में चोट है लेकिन खगेन मुर्मु की हालत इतनी अच्छी नहीं है। अभी तक उन्हें बात करने में दिक्कत हो रही है, टीएमसी कार्यकर्ताओं और गुंडों द्वारा फेंके गए पत्थर से उनके चेहरे की एक हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने उन्हें लंबे आराम की सलाह दी है... कानून व्यवस्था राज्य का विषय है इसलिए इस पर हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन अगर हालात और बिगड़ते है तो हमें अदालत जाना होगा ताकि सीबीआई जांच हो, जिस व्यक्ति पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, वह एसटी समुदाय से है, इसलिए मुझे लगता है कि खगेन मुर्मु पर हमला करने वालों पर एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम लगाया जाना चाहिए। इस हमले पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, उत्तर बंगाल में जो हुआ उससे टीएमसी का कोई लेना-देना नहीं है। भाजपा को यह विश्लेषण करना चाहिए कि उनके सांसदों और विधायकों के खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। जनता उनसे नाराज क्यों है?... हम इसकी निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खगेन मुर्मु से मुलाकात की और हमले की निंदा की। वहीं भाजपा नेता दिलीप घोष ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, टीएमसी की वजह से बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है... बागेश्वर बाबा की सभा ममता बनर्जी ने रद्द कर दी है... टीएमसी के लोगों ने नौ जगहों पर वक्फ दहन कार्यक्रम को जबरन रुकवा दिया है...

पीलीभीत के गांव रसिया खानपुर में बुखार का कहर, अब तक सात लोगों की मौत; 200 से अधिक बीमार

पीलीभीत पीलीभीत के बीसलपुर तहसील के रसिया खानपुर गांव में बीते 24 घंटों में बुखार से तीन लोगों की मौत से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। दो सौ से अधिक लोग बुखार से पीड़ित हैं, जिनका उपचार चल रहा है। लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि सिस्टम मौतों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसका नतीजा गांव के लोग भुगत रहे हैं। एसडीएम नागेंद्र पांडेय ने मंगलवार को दोपहर गांव रसिया खानपुर पहुंचकर स्थिति को परखा तो वहां स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ नहीं मिला। इसपर उन्होंने नाराजगी जताई। कुछ देर बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने गांव में शिविर लगा दिया। पिछले दिनों जिले में हुई भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद बीसलपुर तहसील क्षेत्र के कई गांवों भी बाढ़ की जद में आए थे। इसमें रसिया खानपुर गांव भी शामिल था। गांव में जलभराव की स्थिति बनी थी। बाढ़ के बाद जलभराव की स्थिति तो सामान्य हो गई, लेकिन संक्रमण तेजी के साथ पनपने लगा और बीमार फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 10 दिनों में सैकड़ों लोग बुखार से ग्रस्त हो गए। स्थिति

गंभीर होने पर बरेली और शाहजहांपुर में ले जाकर मरीजों को भर्ती कराया गया। गांव में झोलाछापों के क्लीनिक भी मरीजों से भरने लगे। ग्रामीणों के अनुसार यही वजह रही कि पिछले 10 दिनों में सात लोगों की मौत बुखार से हुई है। निजी अस्पतालों की जांच रिपोर्ट में भी बुखार की पुष्टि हुई लेकिन पूर्व में हुई चार मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच के नाम पर बुखार की बात को नकारते हुए अलग-अलग बीमारियों से मौत होने का दावा किया गया। मंगलवार को गांव के अल्लू खान की पुत्री सकीना, 60 वर्षीय पूती बेगम व रेहान हुसैन (22) पुत्र एजाज हुसैन की बुखार से मौत हो गई। मंगलवार को ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के विरोध में प्रदर्शन किया। गांव रसिया खानपुर में मंगलवार को तेज बुखार से तीन लोगों की मौत होने की जानकारी मिलने पर एसडीएम, कोतवाल संजीव शुक्ला के साथ गांव में पहुंचे। जहां मृतकों के घर जाकर अफसरों ने जानकारी की। घर वालों ने बताया कि उनके परिजनों की तेज बुखार से ही मौत हुई है। इसके बाद एसडीएम स्वास्थ्य शिविर की स्थिति परखने को उच्च प्राथमिक विद्यालय गए, लेकिन मौके पर शिविर लगा हुआ नहीं मिला। इसपर उन्होंने नाराजगी जाहिर की तो दोपहर बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने आयुष्मान केंद्र में स्वास्थ्य शिविर लगाया।

अखिलेश यादव के कार्यक्रम में हुआ बदलाव, पहले बरेली और फिर आजम खां से मिलने रामपुर जाएंगे

लखनऊ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बरेली और रामपुर के दौरे पर हैं। अब से कुछ ही देर में वह लखनऊ एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से बरेली जाएंगे और वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। यहां से वो रामपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे। बता दें कि पहले वह बरेली से रामपुर के लिए सड़क मार्ग से जाने वाले थे पर अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। रामपुर में वह पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है। बरेली में अखिलेश यादव पिछले दिनों पुलिस लाठीचार्ज की घटना और उसके बाद उपजी स्थिति पर भी स्थानीय कार्यकर्ताओं व नेताओं से जानकारी लेंगे। इसके पहले, अखिलेश यादव के आगमन को लेकर मंगलवार को प्रशासन दिनभर तैयारियों में जुटा रहा। अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक सपा मुखिया बुधवार को दोपहर करीब एक बजे रामपुर पहुंचेंगे। वह सीधे सपा नेता आजम खां से मिलने के लिए पहुंचेंगे। यहां वह करीब एक घंटे तक सपा नेता आजम खां से मुलाकात करेंगे। आजम खां के करीबियों की मानें तो घंटे भर की मुलाकात के दौरान दोनों ही नेता आपस में आपसी गिले शिकवे दूर करेंगे।

अखिलेश आजम की सेहत का हाल जान भी जानेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर सपाइयों के साथ ही प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई हैं। प्रशासन की ओर से तीन मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके साथ ही सीओ को भी सुरक्षा के लिहाज से लगाया गया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं।

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मिली वाई कैटेगरी सुरक्षा

नई दिल्ली भोजपुरी सुपर स्टार पवन सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है. आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाई है. इस दौरान सीआरपीएफ के कमांडो पवन सिंह की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे. भारत में VVIP सुरक्षा की अलग-अलग श्रेणियां होती हैं. इसमें Z+, Z, Y+ और वाई कैटेगरी. वाई कैटेगरी में आम तौर पर 8 से 11 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं, जिनमें CRPF या CISF के प्रशिक्षित कमांडो शामिल होते हैं. ये कमांडो व्यक्ति की निजी सुरक्षा, यात्रा, इवेंट और पब्लिक अपीयरेंस के दौरान साथ रहते हैं. पवन सिंह के मामले में गृह मंत्रालय ने CRPF की विशेष यूनिट को यह जिम्मेदारी दी है, जो उन्हें देशभर में सुरक्षा मुहैया कराएगी. सितंबर महीने में बाबा खान के गुंडों ने पवन सिंह को खुलेआम धमकी दी थी. इस धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें बाबा खान के गुंडे कहते नज़र आया था कि दम है तो बाबा खान के सामने आकर कुछ बोलकर दिखाओ. वीडियो सामने आने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खतरे की गंभीरता का आकलन किया और गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजी. इसी रिपोर्ट के आधार पर पवन सिंह को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है. पवन सिंह सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं हैं, वे राजनीति में भी सक्रिय हैं. वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जिससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था. अब पार्टी ने उन्हें अपने पाले में कर लिया है और पवन सिंह को बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में पेश करने की रणनीति बनाई जा रही है।

करूर भगदड़ मामले में 10 अक्तूबर को सुनवाई, स्वीकार हुई अभिनेता विजय की पार्टी की याचिका

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने तमिल अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 10 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका पार्टी के महासचिव आधव अर्जुना ने दाखिल की। इसमें करूर भगदड़ हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र जांच पैनल से कराने की मांग की गई है। याचिका को अधिवक्ता दीक्षा गोहिल, प्रांजल अग्रवाल और यश एस विजय के माध्यम से दायर की गई है। इसमें मद्रास हाईकोर्ट के तीन अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अदालत ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि हाईकोर्ट ने खुद अपने आदेश में पुलिस जांच की स्वतंत्रता पर संदेह व्यक्त किया था, फिर भी उसने केवल तमिलनाडु पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनी एसआईटी को जांच की जिम्मेदारी दे दी, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

जुबीन गर्ग मौत मामले में सिंगर का चचेरा भाई गिरफ्तार

नई दिल्ली मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में जांच चल रही है। इस बीच खबर है कि उनके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, सिंगापुर यॉट पार्टी में जुबीन के साथ वह भी शामिल थे। दरअसल, सिंगर जुबीन गर्ग के चचेरे भाई संदीपन पुलिस सेवा में कार्यरत हैं। इस पूरे मामले में अभी तक कुल पांच गिरफ्तारी हुई हैं। जुबीन गर्ग 20 सितंबर से सिंगापुर में होने वाले तीन दिवसीय नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। 52 साल के गायक जुबीन गर्ग की मौत पिछले महीने सिंगापुर के एक याट में पार्टी के दौरान समुद्र में तैरने गए थे, जहां उन्हें पानी में औंधे मुंह तैरते हुए मृत पाए गए। जुबीन गर्ग की मौत के बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगर के साथ ही उनके चचेरे भाई संदीपन सिंगापुर गए थे। वह यॉट पार्टी में भी मौजूद थे।

26/11 में सेना को किसने रोका, कांग्रेस जवाब दे -मोदी

चिदंबरम के बड़े खुलासे से बवाल

मुंबई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17 साल पहले हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी को घेरा। उन्होंने मुंबई आतंकी हमले के बाद तत्कालीन सरकार की नीति को कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने कहा, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ-साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए, 2008 में आतंकियों ने मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना। लेकिन तब जो कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, उसने कमजोरी का संदेश दिया और आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए।

कांग्रेस सरकार ने देश की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोका

बकौल प्रधानमंत्री मोदी, हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता, जो कांग्रेस के शासनकाल में देश के गृहमंत्री रह चुके हैं, ने एक साक्षात्कार में बड़ा खुलासा किया है कि 2008 के मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं, पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थीं। पूरा देश भी यही चाहता था, लेकिन किसी दूसरे देश के दबाव में कांग्रेस सरकार ने देश की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया।

अब भारत दमदार जवाब देता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखी ताकत

पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को बताना होगा कि वह कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया और मुंबई व देश की भावना से खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा, हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है। यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है।

भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी पर बोले पीएम मोदी

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ। मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। ये एयरपोर्ट, इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी

हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने इसकी अहमियत को रेखांकित करते हुए कहा, इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और पश्चिम एशिया के सुपरमार्केट से भी जुड़ पाएंगे।

सरकार से कांग्रेस पार्टी ने भी पूछे तीखे सवाल

इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 30 सितंबर 2025 को जारी ताजा अधिसूचना में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ओमान, तुर्किए और इजराइल जैसे देशों के नाम भी शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा, देखिए, कूटनीतिक माहौल कितनी जल्दी बदलता है और कूटनीतिक झटके कितनी तेजी से बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव ने दोनों अमेरिकी अधिसूचनाओं की प्रतियां साझा करते हुए कहा कि यह भारत की विदेश नीति की असफलता का संकेत है।

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का भव्य उद्घाटन

मुंबई के लोगों का लंबे समय से इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का भव्य उद्घाटन कर दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, मुंबई में आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। कांग्रेस की कमजोरी से कई जानें गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि अब मुंबई को पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिल गई है, जिससे शहर में सफर आसान होगा और लोगों का समय बचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पहले की सरकार ने इस कार्य को रोक रखा था, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार ने विकास को नया आयाम दिया है। उन्होंने उड़ान योजना के माध्यम से किसानों सहित सभी नागरिकों को होने वाले लाभ का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मुंबई को भारत के सबसे वाइब्रेंट और आर्थिक राजधानी के रूप में प्रदर्शित करते हुए कहा कि युवा हमारी ताकत हैं और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। उन्होंने 2008 के आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस सरकार ने कमजोर संदेश दिया था, जबकि वर्तमान सरकार सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई में दृढ़ है। पीएम मोदी ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत आज घर में घुसकर आतंकवाद को कठोर जवाब देने में सक्षम है। नए एयरपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।